सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹02

# स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, बुधवार, 16 जुलाई, 2025
वर्षः 02, अंकः 191, पृष्ठः 8+4

मास्को को ट्रंप की धमकी की परवाह नहीं

» Pg 12

**इनसाइड** केडीए में वीसी मदन सिंह गर्ब्याल का मास्टर स्ट्रोक.. » Pg 03

# हाईकोर्ट के आदेश पर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का निलंबन निरस्त

## वर्तमान सीएमओ डॉ. उदयनाथ को श्रावस्ती में अपर सीएमओ के पद पर भेजा

» अनूप अवस्थी, स्वराज इंडिया

**कानपुर।** डीएम-सीएमओ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से विवाद के बाद सस्पेंड किए गए सीएमओ डा. हरिदत्त नेमी को हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने बुधवार को बहाल कर दिया है। वर्तमान सीएमओ डा. उदयनाथ को पूर्व तैनाती श्रावस्ती जनपद में अपर सीएमओ के पद पर भेज दिया गया। ऐसे में आसार हैं कि डॉ. नेमी कानपुर में फिर से सीएमओ के पद पर कुर्सी संभाल सकते हैं।

दरअसल कानपुर डीएम-सीएमओ विवाद पर जमकर राजनीति हुई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित कई विधायकों ने सीएमओ डा. नेमी के पक्ष में पत्र लिखे थे लेकिन वहीं कुछ सत्ताधारी विधायकों ने सीएमओ के खिलाफ पत्र शासन को भेजे थे। इसके बाद 19 जून 2025 को सीएमओ डॉ. नेमी को विभागीय अनियमितताओं में आरोपित करके सस्पेंड कर दिया गया था। कानपुर में नए सीएमओ के तौर पर श्रावस्ती जनपद के अपर सीएमओ डा. उदयनाथ को यहां पर तैनाती दी गई थी। इस कार्रवाई के खिलाफ डा. हरिदत्त नेमी हाईकोर्ट की लखनउ बेंच में याचिका दाखिल की थी। डॉ. नेमी बनाम उप्र सरकार के वाद में हाईकोर्ट ने डा. नेमी के निलंबन पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद सीधे कानपुर पहुंचकर सीएमओ की कुर्सी पर बैठ गए थे लेकिन शासन से आर्डर नहीं आने की बात कहकर अगले दिन सीएमओ कार्यालय से वापस कर दिया गया था। इस तरह से कानपुर में प्रशासनिक माहौल खराब रहा था।

**मुद्दा बना चर्चा :** अधिकारियों की लडाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुटकी लेते हुए कहा था कि उप्र में डबल इंजन की सरकार में डिब्बे भी टकरा रहे हैं।

» डीएम से विवाद के बाद डॉ. नेमी सस्पेंड, इसके खिलाफ गए थे वह हाईकोर्ट

» अवमानना पर 17 जुलाई को सुनवाई से पहले शासन ने जारी किए पत्र

### तत्काल जारी हुए पत्र

डा. हरिदत्त नेमी को जब सीएमओ के पद पर ज्वाइन नहीं करने दिया गया तो वह फिर हाईकोर्ट पहुंचे। यहां पर अवमानना वाद दायर कर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य उप्र, डीएम कानपुर, डॉ. उदयनाथ, एडीएम सिटी राजेश कुमार और एसीपी अभिषेक पांडेय को पार्टी बनाया। इस पर हाईकोर्ट ने 17 जुलाई 2025 को सुनवाई की तिथि तय की है। हालांकि 16 जुलाई को पत्र जारी किए हैं।

**बयान बदलने का बना रहे दबाव**

## छांगुर के करीबियों ने एटीएस के गवाह को धमकाया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**बलरामपुर।** अवैध धर्मांतरण व देश विरोधी गतिविधियों के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के करीबी अभी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं। एटीएस की जांच और कार्रवाई के बाद भी छांगुर के सहयोगी लोगों को धमका रहे हैं। एटीएस की जांच में गवाही देने वाले हरजीत कश्यप को कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। हरजीत की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरजीत का आरोप है कि तीनों छांगुर के खास लोग हैं और उन पर बयान बदलने का दबाव बना रहे हैं, मना करने पर जान से मारने की धमकी दी है।

**कार्रवाई** वर्ष 2010 से 2012 के बीच 91200 रुपये की जगह 2.30 लाख का किया भुगतान

# 7.95 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में रिटायर्ड पीसीएस गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**लखनऊ।** 7.95 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण विभाग के पूर्व निदेशक मिश्रीलाल पासवान को महानगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने यह कार्रवाई रुड़की की गुरु नानक एजूकेशन ट्रस्ट को नियम विरुद्ध छात्रवृत्ति देने के मामले में की है।

वर्ष 2010 से 2012 के बीच हुए इस घोटाले में ईओडब्ल्यू की ओर से यह पहली गिरफ्तारी है। पीसीएस अधिकारी मिश्रीलाल वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त हो गए थे। 2010 से 2012 के बीच समाज कल्याण निदेशालय में तैनात निदेशक मिश्रीलाल और अन्य कार्मिकों ने गुरु नानक एजूकेशन ट्रस्ट के तत्कालीन ट्रस्टी के साथ मिलीभगत कर छात्रवृत्ति घोटाला किया था। छात्रवृत्ति के निर्धारित 91,200 रुपये के स्थान पर 2.30 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। ट्रस्ट के साथ मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेजों के जरिये छात्रवृत्ति के करीब 7.95 रुपये हड़पे गए थे। पीजीडीएम कर रहे 336 छात्रों को निर्धारित राशि से अधिक छात्रवृत्ति दी थी। 2019 को थाना एसआईटी, लखनऊ में 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

**छात्रवृत्ति के रुपये हड़पे :** छात्रवृत्ति घोटाले में शासन के निर्देश पर एसआईटी ने केस दर्ज किया था, जिसमें तत्कालीन समाज कल्याण निदेशक मिश्रीलाल पासवान के साथ तत्कालीन पटल सहायक शिक्षा अनुभाग धर्मेंद्र सिंह, अधीक्षक शिक्षा अनुभाग डीके गुप्ता व अनिल उपाध्याय (अब मृत), योजना अधिकारी डॉ. मंजूश्री श्रीवास्तव व गुरुनानक एजूकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी गुरु सिमरन सिंह चड्ढा को नामजद किया था।

जांच में सामने आया था कि ट्रस्ट में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के यूपी के मूल निवासी छात्र-छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि वर्ष 2010-11 व वर्ष 2011-12 में समाज कल्याण निदेशालय से ली गई थी।

# बिल्हौर सीएचसी में गैरहाजिरी का खुला खेल!

**» सीएमओ ने वेतन कटौती के दिए निर्देश**

## सीएमओ के निरीक्षण में एक डॉक्टर समेत 12 कर्मचारी नदारद

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

बिल्हौर (कानपुर)। मंगलवार सुबह करीब आठ बजे जैसे ही मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. उदय नाथ ने बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हो गई। निरीक्षण के दौरान एक डॉक्टर समेत कुल 12 कर्मचारी बिना सूचना के गैरहाजिर पाए गए।

सीएमओ ने अस्पताल की ओपीडी, डेंटल यूनिट, एक्स-रे कक्ष और लैब का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर अधीक्षक धर्मेंद्र गुप्ता भी पहुंचे और उपस्थिति रजिस्टर की जांच की।

रजिस्टर में दर्ज अनुपस्थित कर्मचारियों में एएनएम कविता, फार्मासिस्ट हर्बित, स्टाफ नर्स राजीव, मनु, सुशीला, डॉ. मृत्युंजय, वार्ड बॉय शिवम, एसएन शिवाला, स्टाफ नर्स सर्वेश, शशिबाला शर्मा और एलटी शशिभूषण शामिल थे।सीएमओ डॉ. उदय नाथ ने बताया कि वे बीते एक सप्ताह से अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं दिखा। उन्होंने सख्ती दिखाते हुए गैरहाजिर कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए।

# सभासद बबलू पांडे बीएसपी में शामिल

**» पार्टी के लोगों ने फूल-मालाओं से किया स्वागत**

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

बिल्हौर( कानपुर )। बिल्हौर नगर पालिका के सभासद सत्येंद्र उर्फ बबलू पांडे ने गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया।

पार्टी नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक योगदान और जनपक्षधर छवि को देखते हुए उन्हें बिल्हौर सेक्टर का महासचिव नियुक्त किया है। साथ ही पार्टी ने अजीत सिंह पाल और मनोज कुमार कमल को ओबीसी भाईचारा संयोजक बिल्हौर की जिम्मेदारी सौंपी है।

इस अवसर पर कई अन्य स्थानीय कार्यकर्ता भी पार्टी से जुड़े। बीएसपी नेताओं ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए ऐसे कर्मठ लोगों की ज़रूरत है और पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है।

# भूसाटोली बर्तन बाजार में फिर धंसी सड़क, बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, मरम्मत कराने की मांग

कानपुर। भूसाटोली स्थित बर्तन बाजार में बारिश से सड़क फिर धंस गई। इससे क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। साथ ही हादसे का खतरा भी बना हुआ है।

कानपुर में लगातार बारिश के कारण शहर के भूसाटोली स्थित बर्तन बाजार में सड़क एक बार फिर धंस गई है। इससे क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है और हर समय हादसे का खतरा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, एक दिन पहले ही इस जगह पर सीवर चैंबर बनाकर उसके आसपास गिट्टी, बालू और मलबा भरा गया था, लेकिन बारिश होते ही सड़क का यह हिस्सा धंस गया।फिलहाल, मौके पर जेसीबी से खुदाई का काम शुरू कराया गया है और केबल हटाए जा रहे हैं, जिसके बाद मरम्मत कार्य शुरू होगा। क्षेत्रीय पार्षद आदर्श गुप्ता ने नगर निगम और जलकल विभाग के अधिकारियों से जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने की मांग की है, ताकि लोगों को हो रही परेशानी से निजात मिल सके और किसी बड़े हादसे को टाला जा सके।

# केडीए में वीसी मदन सिंह गर्ब्याल का मास्टर स्ट्रोक

## प्राधिकरण में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल-अवैध निर्माणों पर लगेगा लगाम, महिला अफसरों को मिली कमान

**प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया**

**कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) में अवैध निर्माणों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने प्रवर्तन और विक्रय विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस कदम से जहां लंबे समय से जमे प्रभारियों की जिम्मेदारी बदली गई है, वहीं नई टीम को कार्यभार सौंप कर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया गया है।**

**प्रवर्तन दस्ते से हटाए गए पुराने प्रभारी**

अब तक प्रवर्तन कार्य का जिम्मा संभाल रहे विशेष कार्याधिकारी सत शुक्ला, डॉ. रवि प्रताप सिंह, अजय कुमार और अधिशासी अभियंता संदीप मोदनवाल से यह जिम्मेदारी हटाकर इसे अधिशासी और सहायक अभियंताओं को सौंपा गया है।

जोन 1- नितिन भारद्वाज
जोन 2- संदीप मोदनवाल
जोन 3-अतुल राय
जोन 4- प्रवीण शर्मा

इसके साथ ही प्रवर्तन दस्ते में तैनात सभी पुराने अवर अभियंताओं को हटाकर नए अभियंताओं की नियुक्ति की गई है।

**विक्रय विभाग में महिला अफसरों की एंट्री**

इतिहास में पहली बार केडीए के विक्रय विभाग में महिला अधिकारियों को जोन प्रभारी बनाया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जोन 1- बृजेंद्र उपाध्याय
जोन 2-मीनाक्षी गुप्ता
जोन 3-सत शुक्ला
जोन 4- अर्चना शर्मा (तहसीलदार)

**महत्वपूर्ण योजनाओं पर अलग-अलग अधिकारी नियुक्त**

विश्वबैंक परियोजना और न्यू कानपुर सिटी योजना के तहत भूमि अधिग्रहण और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिम्मा अब डॉ. रवि प्रताप सिंह और अजय कुमार को सौंपा गया है।

भूमि बैंक प्रबंधन का कार्य भी अब जोनवार अधिकारियों को सौंपा गया है।

**फेरबदल से सक्रिय रैकेट में मची खलबली**

इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल से केडीए में वर्षों से सक्रिय कथित रैकेट और गठजोड़ों को झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, कार्य में पारदर्शिता लाने और आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लेने की दिशा में एक सख्त संदेश है।

प्राधिकरण सूत्रों के अनुसार, यह प्रशासनिक पुनर्गठन अभी प्रारंभिक चरण है। आने वाले समय में कर्मचारियों के कार्यभार और जिम्मेदारियों में भी व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है।

# दीप तिराहे पर ई-रिक्शों का चेकिंग अभियान

## » पुलिस बिना क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शे सीज, चालकों में हड़कंप

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**कानपुर।** यातायात पुलिस ने दीप तिराहे पर ई-रिक्शों का चेकिंग अभियान चलाया। जिन ई-रिक्शों पर क्यूआर कोड नहीं लगा है, उन्हें सीज किया गया है।

कानपुर में बेलगाम दौड़ रहे ई-रिक्शों को

नियंत्रित करने और उन्हें निर्धारित रूटों पर चलाने के लिए यातायात विभाग ने दीप तिराहे सहित पूरे शहर में एक बड़ा अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत, बिना क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शों को सीज किया जा रहा है।

बता दें कि यातायात विभाग ने ई-रिक्शा चालकों को दो महीने पहले ही उनके रूट के लिए क्यूआर कोड जारी किए थे। अनुमानित 70 हजार ई-रिक्शों में से मात्र सात हजार ने ही पंजीकरण कराया

और उनमें से भी केवल 1679 चालकों ने क्यूआर कोड हासिल किए।

# सरैया दस्तम गांव की बदहाली पर बीएसपी ने लिया संज्ञान

» मायावती के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल का दौरा

» गांव की समस्या को लेकर प्रशासन से टकराव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर ब्लॉक के सरैया दस्तम खा गांव में फैली गंदगी और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों के बाद बीएसपी सुप्रीमो सुश्री मायावती ने मामले को संज्ञान में लेते हुए गांव में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा।

इस प्रतिनिधिमंडल में मंडल प्रभारी आनंद कुरील, पूर्व विधानसभा प्रभारी एडवोकेट विनय कुमार गौतम, जीतू पैंथर, संदीप कुरील, वीरेंद्र बहुजन, विधानसभा अध्यक्ष रमेश पाल, मनोज कमल, अजीत सिंह पाल, एडवोकेट धर्मेंद्र, बीबीएफ संयोजक राव जी और एडवोकेट रवि गौतम शामिल रहे।

प्रतिनिधि मंडल ने गांव पहुंचकर कीचड़, गंदगी और सफाई व्यवस्था की गंभीर स्थिति का जायज़ा लिया। इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मायावती जी को भेज दी गई है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, संगठन हर स्तर पर संघर्ष करता रहेगा।

बिल्हौर विधानसभा के पूर्व प्रभारी विनय गौतम ने बताया कि मोहर्रम के मौके पर जब ताज़िया का जुलूस गांव के तय रूट से निकला,तो गंदगी और कीचड़ के बीच से होकर जाना पड़ा।

इस दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसे देखकर बहन जी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उसके बाद बीडीओ ने गांव पहुंचकर सचिव को सफाई के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है प्रधान जी को गांव से कोई लेना देना नहीं है। गांव की इतनी बड़ी समस्या प्रधान को नज़र नहीं आती। कुछ ग्रामीणों ने तंज कस्ते हुए कहा जिला पंचायत सदस्य तो राजा साहब हैं।

**गांव वाले ही रोक रहे निर्माण-महमूद**

बारांडा भाजपा जिला पंचायत सदस्य महमूद का कहना है गांव में नाला पास हो चुका है, लेकिन कुछ ग्रामीण खुद ही निर्माण में बाधा डाल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। मामले में ग्राम प्रधान से सम्पर्क नहीं हो सका।

**चौपाल लगाकर करेंगे संवाद- नन्दलाल पाल**

भाजपा के कार्यकर्ता नन्दलाल पाल,जो बरांडा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद कई कार्यकर्ताओं के साथ गांव गया था।

कुछ ग्रामीण नाला निर्माण का विरोध कर रहे हैं। मैंने विधायक जी को पूरे मामले से अवगत करा दिया है। जल्द ही गांव में चौपाल लगाकर लोगों से संवाद करूंगा।

# युवक को डंपर ने रौंदा, घर से पुलिस लाइन जाते समय हुआ हादसा

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

कानपुर। परिजनों का आरोप है कि राहगीरों ने शोर मचाया तो पकड़े जाने के डर से चालक ने डंपर भगा दिया, जिसमें युवक बाइक समेत फंसकर करीब पांच सौ मीटर दूर दासूकुओं तक घिसटता चला दिया। हादसे में सुमित को मौके पर मौत हो गई।

कानपुर में कानपुर-सागर हाईवे पर बाइक सवार प्राइवेट कुक को मंगलवार सुबह डंपर ने रौंद दिया। राहगीरों के शोर मचाने पर डंपर चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। उधर, युवक डंपर में फंस गया और 500 मीटर तक घिसटता चला गया। इससे शव क्षतविक्षत हो गया।

नौबस्ता के निवासी सुमित कुशवाहा (33) पुलिस राजीव विहार पुलिस लाइन की मेस में प्राइवेट कुक थे। वह पुलिस कर्मियों के लिए खाना बनाते थे। पिता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि रोज की तरह मंगलवार सुबह करीब आठ बजे इकलौता बेटा सुमित बाइक से पुलिस लाइन जा रहा था।

हाईवे पर धोबिन पुलिया मेट्रो के पास हमीरपुर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने सुमित को पीछे से टक्कर मार दी। परिजनों का आरोप है कि राहगीरों ने शोर मचाया तो पकड़े जाने के डर से चालक ने डंपर भगा दिया जिसमें युवक बाइक समेत फंसकर करीब पांच सौ मीटर दूर दासूकुओं तक घिसटता चला दिया। हादसे में सुमित को मौके पर मौत हो गई। मां सुशीला और दो बहनो का रोकर बुरा हाल है। युवक की बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

नौबस्ता इंस्पेक्टर शरद तिलारा के अनुसार परिजनों की तहरीर पर अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।सुबह आठ बजे हादसा, 2:40 बजे पहुंचे पंचनामे के कागज

परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसा सुबह आठ बजे हुआ था। इसके बाद पुलिस की सुस्त कार्रवाई के कारण सुमित के पंचनामा के कागज दोपहर करीब 2:40 पर पुलिसकर्मी लेकर पहुंचे। देरी से शुरू हुई पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया के कारण परिजनों ने रोष जताया। शाम करीब 4:30 बजे परिजन शव को लेकर चले गए।

## सम्पादकीय

# संयमित न हुई अभिव्यक्ति तो अंकुश

कथित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति के चलते उपजी विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश की जरूरत बताते हुए देश की शीर्ष अदालत ने आत्म-नियमन की जरूरत बतायी है। दरअसल, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ, एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिस पर धर्म विशेष के देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत का कहना था कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का मूल्य समझना चाहिए। साथ ही इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आत्म-संयम बरतना चाहिए। कोर्ट ने चेताया है कि यदि सोशल मीडिया पर विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगता तो सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। जो एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। निस्संदेह, समाज में विद्वेष व नफरत फैलाने वाले संदेश समरसता के भारतीय परिवेश के लिये गंभीर चुनौती बने हुए हैं। यही वजह है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि वह नियमन के लिये दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। दरअसल, अदालत का मानना था कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मिली आजादी असीमित कदापि नहीं है। यदि उससे सामाजिक समरसता में खलल पड़ता है तो सरकार को दखल देने का मौका मिलता है। जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिये अच्छा संकेत नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को सरकार नियंत्रित करे। सही मायनों में लोगों को समझना चाहिए कि देश की एकता व अखंडता बनाये रखना मौलिक कर्तव्य ही है। अदालत ने इस बाबत सवाल भी किया कि नागरिक स्वयं को संयमित क्यों नहीं कर सकते? कोर्ट का मानना था कि लोग तभी अभिव्यक्ति की आजादी का आनन्द ले सकते हैं जब यह संयमित ढंग से व्यक्त की जाए। शीर्ष अदालत की पीठ का मानना था कि नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए, तभी समाज में नफरत से मुकाबला किया जा सकता है। तभी हम गंगा-जमुनी संस्कृति के समाज का निर्माण कर सकते हैं।

वैसे कई राज्यों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के नियमन को लेकर सरकारी कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कई जगह विचारों की अभिव्यक्ति व कार्टून आदि बनाने को राजनीतिक दुराग्रह बताते हुए लोगों को गिरफ्तार तक किया गया है। जिसे सत्ताधीशों द्वारा बदले की भावना से की कार्रवाई बताया जाता रहा है। आरोप लगाया जाता रहा है कि सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के अनुरूप अमर्यादित अभिव्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन दूसरे राज्य में अन्य राजनीतिक दल की सरकार में यही अभिव्यक्ति अपराध बन जाती है। कहा जाता रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी द्वारा किसी मर्यादा को भंग करना घटिया या आपत्तिजनक तो हो सकता है लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। इसे कानून के आलोक में देखा जाना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों द्वारा सोशल मीडिया मंच का जमकर दुरुपयोग किया जाता रहा है। वहीं लोगों का कसूर यह है कि दल विशेष के एजेंडे वाली सामग्री को वे बिना पढ़े, दूसरे लोगों व समूहों में शेयर कर देते हैं। दरअसल,आम नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उनका संयमित व्यवहार कैसा होना चाहिए। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही सामग्री की कितनी संवेदनशीलता है।

# शुभमन के उभार से भारतीय क्रिकेट में शुभ संकेत

प्रदीप मैगजीन

**किसी वरिष्ठ खिलाड़ी की गैरमौजूदगी में, भारतीय टीम इंग्लैंड के चुनौतीपूर्ण दौरे पर थी जिसकी कप्तानी नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल कर रहे थे। टीम में कोई 'मार्गदर्शक' खिलाड़ी नहीं था जिससे आशंकाएं भी थीं। हार-जीत अपनी जगह लेकिन लीड्स मैदान में कुशल बल्लेबाज गिल ने कप्तान की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उसकी मुस्कान व विनम्रता अब क्रिकेट प्रेमियों को भाएगी।जब जीत की खुशी से ज्यादा हार का डर बन जाए, तो मानस पर संदेह की परत चढ़ जाती है। सफलता की राह में बाधाएं खड़ी करने वाले इस स्व-निर्मित भय को मिटाने के लिए असाधारण प्रयासों की जरूरत पड़ती है। जब सफलता और स्टारडम की एक समान चाहत रखने वाली भारतीय टीम का कप्तान शुभमन गिल को नियुक्त किया गया, तो पूरा भारत आशंकित था। एक ऐसे समाज के लिए जिसे शून्यता में रहने से डर लगता है, वह शून्यता जो 'दैवीय प्रकाश पुंज' के न रहने से बनती है, ऐसे में बेचैन बने अपने अस्तित्व को कुछ मायने और सार देने के लिए एक 'देवदूत' की बेतरह आकांक्षा करता है।**

भारत के क्रिकेट प्रेमी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना उनकी दुनिया कैसी दिखेगी।उनका 'परम प्रिय' कोहली दूर चला गया था, जिसने सालों तक एक राजा या मालिक की तरह 'सल्तनत' पर बादशाहत की। हमारे समय की सबसे प्रभावशाली क्रिकेट शख्सियत, जिसकी प्रशंसक पूजा करते हैं और टेलीविजन चैनलों का सबसे प्रिय। उसने इंग्लैंड में अपने साथियों के साथ टेस्ट मैच में जूझने की बजाय विंबलडन में टैनिस मैच देखना पसंद किया। क्या पता, टेस्ट रन औसत सूची में नीचे फिसलने का डर और लोगों की अपेक्षाओं का बोझ, रन बनाने और सैकड़ा मारने से मिलने वाली खुशी पर हावी हो गया हो।रोहित शर्मा, सितारों वाली नखरेबाज़ी से सदा दूर, आम लड़के की छवि वाला, पर जिसने क्रिकेट में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया। उसे यह अहसास करने में थोड़ा वक्त लगा कि उसका वक्त चुक गया है, आखिरकार, इंग्लैंड दौरे के लिए टीम चयन से एक दिन पहले उसने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ऐसे में किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक की गैरमौजूदगी में, इंग्लैंड के कठिन और चुनौतीपूर्ण दौरे पर भारतीय टीम दिशाहीन स्थिति में पहुंच सकती था। घर में और विदेशों में, भारतीय टीम को मिली खलाबद्ध हार की पृष्ठभूमि में, यह आशंका निराधार नहीं थी।भारत ने लीड्स के मैदान में रक्षात्मक मानसिकता के साथ पहले टेस्ट मैच में कदम रखा, जो टीम चयन में परिलक्षित हो रहा था। जो आदमी अब सब फैसले लेने और टीम नियंत्रक प्राधिकारी के तौर पर पीछे बचा, वह था विवादास्पद कोच गौतम गंभीर। उसकी इस निर्विवाद शक्ति के पीछे ज्यादा बड़ा कारक है सत्तारूढ़ पार्टी का पूर्व सांसद होना बजाय इसके कि बतौर क्रिकेटर उसकी सम्मानजनक साख रही है या रणनीति या मानव-प्रबंधन कौशल की अच्छी समझ है, हालांकि कोलकाता नाइट राइडर के टीम-कोच के रूप में आईपीएल में वह काफी सफल रहा।फुटबॉल के विपरीत, क्रिकेट में टीम का चेहरा इसका कप्तान होता है न कि कोच या मैनेजर। एक ऐसे खेल में, जो पांच दिन चलता है और मैदान में लिए जाने वाले फैसलों को दूर से बैठकर प्रेषित करना मुश्किल है, कप्तानी का काम कोच के आदेशों से नहीं चल सकता। खिलाड़ियों को संभालने एवं अगुवाई करने का बोझ पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के एक छोटे से गांव के एक युवा के कंधों पर आन पड़ा।ग्रामीण पंजाब का एक लड़का, जिसके कृषक पिता ने खेती के साथ-साथ बेटे को पेशेवर क्रिकेटर बनाने में मेहनत की। शुभमन एक रूढ़िवादी आक्रामक, आवेगी व बिना सोचे-समझे काम करने वाले चरित्र जैसा नहीं है। भारतीय क्रिकेट जगत में उत्तर भारतीय बनाम शेष भारतीय विभाजन को लेकर खूब कहानियां रही हैं।

# लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाने का वक्त

**आयुक्त की काल्पनिक चिट्ठी**

मनोज चितन

**पुनरीक्षण कार्य लोगों का नाम काटने और शक्तिहीन करने वाला प्रतीत हो रहा है। दूरगामी परिणामों वाले इतने विशाल काम को, इतने कम समय में करने का प्रयास तक आपदा का नुस्खा बन सकता है।प्रिय मुख्य चुनाव आयुक्त! मैं समय के गलियारे के छोर से आपको यह चिट्ठी लिख रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे हमारे गणतंत्र के एकदम प्रारंभिक वर्षों में यह सुनिश्चित करने का पावन काम सौंपा गया था कि प्रत्येक भारतीय, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, वर्ग या क्षेत्र का हो, मुक्त और बेखौफ होकर अपना वोट डाल सके।**

जब मैंने 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव करवाया था, तब गणतंत्र शैशव काल में था, विभाजन के जख्म ताजा थे, निरक्षरता से बोझिल और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विचार से अनभिज्ञ। फिर भी, भारतीय जनता ने चुनावी प्रक्रिया में अटूट विश्वास जताया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इसे संचालित करने वाली संस्था निष्पक्षता, दृढ़ता और कार्यपालिका से पूर्ण आजादी के साथ काम कर रही है।आज, जरूरी है कि यह विश्वास डगमगाए नहीं, क्योंकि बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में आई हालिया रिपोर्टें बेहद परेशान करने वाली हैं। आरोप हैं कि यह प्रक्रिया गरीबों, भूमिहीनों और सामाजिक रूप से हाशिए के लोगों को असमान रूप से प्रभावित कर रही है, जिनके लिए मतदान का अधिकार अक्सर सशक्तीकरण का एकमात्र वास्तविक साधन रहा है।वहां चल रहा पुनरीक्षण कार्य लोगों का नाम काटने और शक्तिहीन करने वाला प्रतीत हो रहा है। दूरगामी परिणामों वाले इतने विशाल काम को, इतने कम समय में करने का प्रयास तक आपदा का नुस्खा बन सकता है। आप यह काम एक ऐसे राज्य में कर रहे हैं जहां से दूसरे राज्यों में प्रवासी कामगार बनने वालों की संख्या बहुत अधिक है। जिसका भूगोल कुछ महीने बाढ़ से अस्त-व्यस्त रहता है। आप पर सूचना प्रकटीकरण में कंजूसी, चर्चाओं और संवाद में अड़ियल रवैया अपनाने और सबसे दुखद यह कि सार्वजनिक संवाद में आपके द्वारा लड़ाकू रुख रखने के आरोप लगते हैं। इन दिनों आलोचकों को चुप कराने के लिए नियम-पुस्तिका का वास्ता देना एक प्रकार से नैतिकतावादी हथकंडा बन गया है। नियम-पुस्तिका न्यूनतम और बुनियादी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए होती है।करोड़ों लोगों पर उनका नाम कटने की चिंता तारी है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के दो हफ़्ते बाद भी, कई लोगों को मतदाता आवेदन फ़ॉर्म तक नहीं मिले हैं। अपनी पात्रता सिद्ध करने को मतदाताओं के एक बड़े हिस्से के पास आपके आयोग द्वारा तय किए गए।

# स्लीपर-एसी में भी जनरल जैसी भीड़

## कई यात्रियों को शौचालय में बैठने को मजबूरी

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**कानपुर। रेलवे जोन मुख्यालय से उत्तर से दक्षिण, पश्चिम और पूर्व को जोड़ने वाली दो सौ से अधिक यात्री गाड़ियों का संचालन होता है। रेलवे ने इंजन से लेकर कोच तक बहुत से बदलाव किए हैं। अब हाईस्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी भी कि है। लेकिन, आम यात्री के लिए अब भी रेल में सफर करना सजा से कम नहीं है।**

आलम यह है कि ट्रेन के टॉयलेट के सामने और अंदर कई घंटे बैठकर यात्रा करना मुसाफिरों की मजबूरी है। मंगलवार को रेल यात्रा का जायजा लेने निकली चेतना टीम ने जो दृश्य देखे, जो किसी यातना से कम नहीं नजर आए। गोरखपुर जंक्शन से पनवेल (नवी मुंबई) तक चलने वाली 15065 पनवेल एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर और जनरल कोच की स्थिति एक जैसी थी। क्षमता से अधिक जनरल कोच की सीट पर छह सात से आठ लोग बैठे थे। ऐसा ही आलम स्लीपर की सीटों पर भी था। कोच की गैलरी से लेकर दरवाजे और टॉयलेट तक यात्री खड़े और बैठे थे।

भीड़ इतनी थी कि लोग स्लीपर कोच में भी ठसाठस भरे थे। इससे जिन यात्रियों के पास कंफर्म बर्थ थी वे भी परेशान थे। गोंडा जा रहे प्रेम कुमार ने बताया कि स्लीपर क्लास में भीड़ जुटती है कि रात में भी सोना मुश्किल होता है। वही ट्रेन के टॉयलेट रुम के अंदर बैठे थे। स्टेशन आते ही दोनों लड़के खड़े हो गए टॉयलेट की खिड़की से खाने की

सामग्री समोसा खरीब खाने लगे। वही एक दृश्य और भी देखने को मिला कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म 6 और 7 पर पनवेल एक्सप्रेस आते ही ट्रेन में तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट से लेकर लाइटर आदि सामग्री बिक रही थी। ऐसे में स्टेशन पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी मॉनिटिंग सुरक्षा बल कर्मी पर भी सवाल खड़े करती है। नाबालिग लड़के और लड़कियां जो कि अवैध वेंडर है, धड़ल्ले से सामग्री बेच रहे थे। महिला कोच में भी पुरुषों का कब्जा था। इस दौरान एक भी रेल सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आया। देखने वाला कोई नहीं था। ट्रेन से लेकर स्टेशन प्लेटफार्मों में लगातार नजर रखते हैं। अवैध वेंडरों और बेटिकट यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई जब होगी जाती।

## जिले में चलेगा घर-घर दस्तक अभियान, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

- **साफ-सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव में न बरती जाए लापरवाही**
- **डेंगू-मलेरिया से बचाव को हर गली, हर घर तक पहुंचेगी टीम**

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता ही संक्रमण से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को जानकारी दी जाए।**

उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार फॉगिंग, जल निकासी, नालियों की सफाई व एंटी लार्वा दवा के छिड़काव के निर्देश दिए। आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सफाईकर्मी अभियान को जन-जन तक पहुंचाएं।

**नुक्कड़ नाटक से जागरूकता और मॉनिटरिंग के होंगे पुख्ता इंतज़ाम**

जिलाधिकारी ने अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक, प्रचार वाहन, पोस्टर, पंपलेट और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत भवनों पर सूचना सामग्री लगाई जाए। उन्होंने

निर्देश दिए कि ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और सीएचसी प्रभारी नियमित निगरानी करें, जबकि जिला स्तर पर सीएमओ सीधे रिपोर्टिंग करें। डीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई तय होगी। बैठक में एडीएम प्रशासन अमित कुमार, सीएमओ डॉ. एके सिंह, मलेरिया अधिकारी मारुति दीक्षित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

# भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले डीपीआरओ को हटाने की मांग

## विकास भवन में तैनात भ्रष्ट ग्राम पंचायत बाबू और सचिव के खिलाफ एक्शन की मांग, संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन की बैठक में प्रस्ताव

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

**कानपुर। विकास भवन में तैनात एक ग्राम पंचायत सचिव/लिपिक द्वारा दिव्यांग महिला सफाई कर्मचारी से रिश्वत लेने का मामला सामने आने के बाद संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को जल संस्थान परिसर में यूनियन की एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष सुनील सुमन ने की। बैठक में संरक्षक बी.एल. गुलाबिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार जिला पंचायत राज अधिकारी की निगरानी में वर्षों से चल रहा था।**

बैठक में बताया गया कि उक्त ग्राम पंचायत सचिव पिछले 16 वर्षों से अवैध रूप से सफाई कर्मचारियों के पटल पर कार्य कर रहा था और सफाई कर्मचारियों का निरंतर शोषण कर रहा था। पीड़ित कर्मचारियों को अंततः एंटी करप्शन विभाग की शरण लेनी पड़ी।बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि सचिव के सहयोगी कुछ अन्य सफाई कर्मचारी भी लंबे समय से विकास भवन में लिपिकीय कार्यों में अवैध रूप से तैनात हैं। यूनियन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और मांग की कि उन्हें तत्काल हटाकर राजस्व ग्रामों में पुनः नियुक्त किया जाए।बैठक के बाद संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्काल हटाया जाए।विकास भवन में अवैध रूप से संबद्ध सभी सफाई कर्मचारियों को हटाया जाए।यदि मांगों को शीघ्र नहीं माना गया तो मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पंचायत राज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जानकारी दी जाएगी।इस बैठक में बी.एल. गुलाबिया, मो. उस्मान अली शाह, सुनील सुमन, सुशील सागर, रविन्द्र कुमार मधुर, सुनीता देवी, नृपत कुमार, अजीत कुमार वाल्मीकि, वीरू, सनी सहित अन्य सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की।

### गुरुगांव में संकुल शिक्षक बैठक संपन्न

# निपुण भारत लक्ष्य पर हुआ मंथन

- **गणित-किट, विज्ञान प्रयोग और स्कूल चलो अभियान रहे चर्चा में**
- **बच्चों की लय में वापसी और संवाद सुधारने पर शिक्षकों ने साझा किए सुझाव**

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**कानपुर देहात।** महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर न्याय पंचायत गुरुगांव की संकुल शिक्षक बैठक का आयोजन मंगलवार को संविलियन विद्यालय गुरुगांव में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संकुल शिक्षक रजनीश सक्सेना ने की, जबकि संचालन धर्मेन्द्र सैनी ने किया। बैठक में व्यावहारिक स्कूल चलो अभियान, मौखिक भाषा विकास, गणित किट, विज्ञान किट और विद्यालय को निपुण बनाने की रणनीतियों पर विशेष चर्चा हुई।धर्मेन्द्र यादव ने गणित किट के प्रभावी प्रयोग और बच्चों की पुनः विद्यालय वापसी पर संवाद आधारित शिक्षण पद्धति पर चर्चा की। वहीं शैलेन्द्र कटियार ने विज्ञान किट के प्रयोगों को विस्तार से समझाया। बैठक में निपुण लक्ष्य प्राप्ति हेतु लय, संवाद और सहभागिता जैसे आयामों को केंद्र में रखा गया।

बैठक में अमरसिंह, सोमप्रकाश, सिम्मी पटेल, प्रिया श्रीवास्तव, ममता, गुरुप्रसाद, रंजना सचान, सुहानी सचान, रुचि पांडेय, दीपक सचान, संजय द्विवेदी, अमित कुमार, और प्रतीक सचान समेत कई शिक्षकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक चला। शिक्षकों ने मिलकर तय किया कि प्रत्येक विद्यालय को निपुण भारत मिशन के मानकों पर खरा उतारना है।

# गजनेर सीएचसी प्रभारी पर तानाशाही के आरोप, स्टाफ में उबाल

» नर्सों ने लगाए मनमानी ड्यूटी, पक्षपात और धमकी देने के आरोप

» सीएमओ ने जांच के लिए गठित की कमेटी, प्रभारी बोले- आरोप निराधार

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

कानपुर देहात। गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पुनीत पाण्डेय की कार्यशैली को लेकर स्टाफ नर्सों में जबरदस्त नाराजगी है। जून माह के ड्यूटी रोस्टर को लेकर स्टाफ ने अधीक्षक पर मनमानी, पक्षपात और दबंगई के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टाफ नर्सों

**का कहना है कि कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी जरूरत से ज्यादा लगाई गई, वहीं चहेते स्टाफ को आरामदायक ड्यूटी दी गई।**

नर्स निरंजना देवी की चार बार अकेली ड्यूटी लगाई गई, जबकि प्रियंका अहिरवार को बिना कारण धमकी दी गई।

स्टाफ का आरोप है कि डॉ. पाण्डेय, स्टाफ नर्स अंजली के प्रति पक्षपाती हैं और उन्हें ओपीडी, आईपीडी या पीएमएसएमए डे जैसी जिम्मेदारियों से जानबूझकर दूर रखा जाता है। नर्सों ने यह भी आरोप लगाया कि डॉ. पाण्डेय छुट्टी मांगने पर बहाना बनाते हैं लेकिन अपने मनपसंद स्टाफ को बिना प्रक्रिया अवकाश दे देते हैं। उनका व्यवहार असभ्य है और वह शिकायत सुनने के बजाय कहते हैं मैं जैसा चाहूंगा वैसी ड्यूटी लगाऊंगा, मेरी कोई शिकायत नहीं कर सकता।

सीएमओ डॉ. ए.के. सिंह ने कहा कि मामला गंभीर है। महिला जिला अस्पताल सीएमएस वंदना सिंह की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी गई है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

वहीं सीएचसी प्रभारी डॉ. पाण्डेय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह मेरी छवि को धूमिल करने की साजिश है। कार्य तो करना ही पड़ेगा। जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा।

# सड़कों पर अन्ना मवेशियों का कब्जा, हादसों का बना सबब

» गजनेर-नवीपुर मार्ग बना पशुओं का अड्डा, जिम्मेदार अधिकारी बने मूकदर्शक

» गौशालाएं कागजों में सजी, एडीओ पंचायत की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

कानपुर देहात (माती)।गजनेर-नवीपुर मुख्य मार्ग इन दिनों अन्ना मवेशियों की सराय बन चुका है। दिन हो या रात, गाय और सांडों के झुंड सड़क पर डेरा जमाए रहते हैं। कभी आपस में भिड़ते, तो कभी राहगीरों के सामने आकर हादसे को न्योता देते नजर आते हैं। आए दिन बाइक और चार पहिया वाहनों के दुर्घटना की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं।

सरवनखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत संचालित अस्थायी गौशाला रामकुटी केवल कागजों में चलती प्रतीत हो रही है। मोहाना, गजनेर और अन्य ग्रामीण चौराहों पर मवेशियों का जमावड़ा बना हुआ है।

अगर कोई इन्हें भगाने की कोशिश करता है, तो ये मवेशी आक्रामक होकर लोगों पर झपटने तक को तैयार रहते हैं। पशुपालन की व्यवस्था पूरी तरह फेल है।

ब्लॉक सरवनखेड़ा के एडीओ पंचायत पर खुलेआम मुख्यमंत्री के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने का आरोप है।

गौशालाओं की निगरानी और व्यवस्था में घोर लापरवाही सामने आई है। जिले के उच्च अधिकारी इसी मार्ग से गुजरते हैं, फिर भी किसी ने अन्ना पशुओं की समस्या की सुध नहीं ली। अव्यवस्था खुद बता रही है कि कागजों में संचालन और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

# सेंट मैरीज़ कॉन्वेंट हाई स्कूल में शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

## गुणों के साथ छात्राओं ने ग्रहण की जिम्मेदारियां

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

कानपुर। सेंट मैरीज़ कॉन्वेंट हाई स्कूल, कैंट में 14 जुलाई को सत्र 2025-26 के लिए शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और उन्हें उनके पदों की जिम्मेदारियों से परिचित कराना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके पश्चात ईश्वर वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कक्षा 10 की छात्राओं ने इस अवसर पर अपनी रचनात्मक प्रस्तुति से जिम्मेदारी के महत्व को इंद्रधनुषी रंगों में खूबसूरती से दर्शाया।

सभी नव-चयनित छात्राएं मार्च करती हुई सभागार में पहुंचीं, जहां उन्हें उनके-उनके पदों के अनुसार बैज और सैश पहनाए गए। समारोह में हेड गर्ल समृद्धि तिवारी, वाइस हेड गर्ल मानवी त्रिपाठी, गेम्स कैप्टन वैभवी सिंह, हेड मार्शल फ़ैजा आलम, नेहरू हाउस कैप्टन कुहू गुप्ता, टैगोर हाउस कैप्टन भूमिका जायसवाल, गांधी हाउस कैप्टन रिद्धिमा कपूर, मैरी वार्ड हाउस कैप्टन मनस्वी बाजपेई सहित अन्य पदाधिकारी छात्राओं ने ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ ली।

विद्यालय की प्रबंधक सिस्टर मैरियन ने छात्राओं को अपने प्रेरणादायक शब्दों से प्रोत्साहित किया। अंत में हेड गर्ल समृद्धि तिवारी ने विद्यालय प्रबंधन और सभी शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।

# बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को हॉफ सीएल देय नहीं

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

कानपुर। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को हॉफ डे सीएल यानी आधे दिन का आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान नहीं है हालांकि मानव संपदा पोर्टल पर हॉफ डे सीएल लेने की व्यवस्था है तो इसका अर्थ है कि यह सबके लिए नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो पोर्टल से हॉफ डे सीएल की व्यवस्था हटनी चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि यदि तकनीकी कारणों से इसे नहीं हटाया जा सकता है और ऐसे अवकाश सभी बेसिक शिक्षकों के लिए नहीं है तो बेसिक शिक्षा के उच्चाधिकारियों द्वारा स्पष्ट आदेश होना चाहिए। यह बताया जाना चाहिए कि पोर्टल पर दिखने वाले कौन-कौन से अवकाश देय हैं। बिना स्पष्ट आदेश के पोर्टल पर दिखने वाले ऐसे अवकाश को जानकारी के अभाव में यदि शिक्षक लेते हैं तो बताते चलें विभिन्न जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ शिक्षक हॉफ सीएल लेकर के घर चले गए हैं जबकि शासन द्वारा जारी प्रावधानों के तहत किसी भी शिक्षक को अर्द्ध दिवस का आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रविधान नहीं है। जौनपुर बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल ने इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं जारी पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में आधे दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का प्रविधान नहीं है अगर किसी को अवकाश की आवश्यकता है।

# दो चेन लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े, दिन दहाड़े की थी वारदात

## तमंचा व लूटी चेन बरामद, अन्य दो की तलाश

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**कानपुर।** घाटमपुर पुलिस ने चेन लूट के मामले में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी गई आधी चेन और एक तमंचा बरामद हुआ है। दोनों पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं और दो अन्य साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

कानपुर में घाटमपुर कस्बे के पचखुरा मोहल्ले में अपना प्लाट देखने आए युवक की चेन लूटने वाले दो शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोनो के पास से आधी आधी चेन व तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनो बड़े अपराधी हैं। वहीं एक पर गैंगस्टर तक लगी हुई है। लूट में शामिल दो अन्य बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है।

थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि 10 जुलाई को कस्बे के पचखुरा मोहल्ले में क्षेत्र के कोटरा निवासी सादिक हुसैन अपना प्लाट देखने आए थे। तभी वहां पर कस्बा निवासी समीर कैड़ा व कोटरा निवासी लवकुश सिंह ने दो साथियों के साथ मिलकर सादिक से मारपीट की और गले में पड़ी चेन लूट ले गए थे। जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की थी।

दो साथी फरार, तलाश में जुटी पुलिस

बताया कि जांच के दौरान सुरागरसी करके समीर कैड़ा और लवकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास आधी आधी चेन भी बरामद हुई है। इसके साथ ही समीर के पास से तमंचा व लवकेश के पास से घटना के समय प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है। बताया कि दोनो पर कई मामले दर्ज हैं। लवकेश पर हत्या का मामला दर्ज है और गैंगस्टर भी लगी हुई है।

# अयोध्या नगर निगम में 45 पार्षदों ने की बगावत

## महापौर-आयुक्त का घेराव, गरजे-बरसे जनप्रतिनिधि

» स्वराज इंडिया संवाददाता

**अयोध्या।** नगर निगम कार्यालय मंगलवार को रणभूमि में तब्दील हो गया, जब शहर के करीब 45 पार्षद एकजुट होकर महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीधे उनके कक्ष में घुस गए। आरोप साफ था विकास कार्यों की अनदेखी, फाइलों को दबाना, और पार्षदों की कोई सुनवाई न होना। दोपहर 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक निगम का माहौल गरमाया रहा। पार्षदों का गुस्सा इतना था कि सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद को हूटिंग कर महापौर कक्ष से बाहर निकाल दिया गया।

विकास कार्यों के लिए नाली, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी जैसे प्रस्ताव महीनों से लटके हैं। पार्षदों का कहना था कि नगर निगम प्रशासन या तो उन्हें नज़रअंदाज़ करता है या उनकी बात को कूड़ेदान में डाल देता है। महापौर से हुई तीखी बहस के बाद एक सप्ताह में कार्यवाही का आश्वासन मिला, लेकिन चेतावनी भी साफदी गई कि अबकी बार सुनवाई नहीं हुई तो इस्तीफा या धरना ही विकल्प होगा। संत कबीर नगर वार्ड के पार्षद चंदन सिंह ने पुराने नजूल मामलों को लेकर सहायक नगर आयुक्त पर सवाल उठाया, जबकि वीर अब्दुल हमीद वार्ड के सलमान हैदर ने जनहित के प्रस्तावों को दबाने का आरोप लगाया। अशफाक उल्ला खां वार्ड के पार्षद रत्नेश पांडेय और अखिलेश पांडेय ने फाइलों में देरी को भ्रष्टाचार से जोड़ा।

**हंगामा नहीं इनहाउस डिस्कसन' हो रहा था–महापौर :** इस बीच महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने हंगामे को 'इनहाउस डिस्कसन' बताते हुए बात को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन पार्षदों की तीव्र नाराजगी नगर निगम की अंदरूनी हलचलों और अफ्सरशाही की कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है।

### खास बातें

- पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पार्षदों का विरोध
- अफ्सरों पर फाइल दबाने और रिश्वतखोरी के आरोप
- पुलिस बुलाने की अफ्वाह से परिसर में तनाव

**होमस्टे बने जरायम के अड्डे**

## युवक ने खाया जहर होम स्टे संचालक को बताया जिम्मेदार

» स्वराज इंडिया संवाददाता

**अयोध्या।** धार्मिक नगरी अयोध्या का बाहरी इलाका दर्शननगर इन दिनों मौत, धोखा और धंधे का अड्डा बनता जा रहा है। अब माधव होमस्टे में ही भोला गुप्ता की आत्महत्या। बता दे कि भोला गुप्ता, जो यात्रियों और पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस बुकिंग का ब्रोकर था, शनिवार की रात माधव होमस्टे के कमरे में जहर खा कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर गया। लेकिन इस आत्महत्या के पीछे जो वजह सामने आई, उसने अयोध्या की गेस्ट हाउस इंडस्ट्री की काली हकीकत को बेनकाब कर दिया।

गौरतलब हो कि भोला द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में लिखा है कि उसी क्षेत्र गेस्ट हाउस के मालिक ने उससे चार लाख उधार लिए थे, जो बार-बार मांगने के बावजूद नहीं लौटाए। अब आत्मसम्मान नहीं बचा, मैं मर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार शिवकुमार है। कोतवाली अयोध्या पुलिस ने आरोपी होम स्टे संचालक को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। सूत्र बताते हैं कि ये मामला सिर्फ उधारी का नहीं बल्कि होम स्टे इंडस्ट्री के भीतर चल रही एक बड़ी आर्थिक और नैतिक अराजकता का हिस्सा है।

**उपेक्षा का शिकार**

**पर्यटन बढ़ाने जैसे तमाम दावों संग शुरू किया जटायु क्रूज सरयू किनारे जंग खा रहा**

# अयोध्या का क्रूज 'जटायु न पानी का ठिकाना, न योजना की दिशा

» स्वराज इंडिया संवाददाता

**अयोध्या।** राम मंदिर निर्माण के साथ ही जब अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की बात हुई, तो सरकार ने एक के बाद एक कई योजनाओं की झड़ी लगा दी। इन्हीं में से एक थी सरयू नदी पर जटायु क्रूज सेवा। सितंबर 2023 में बड़े धूमधाम से इसका उद्घाटन हुआ। दावा था कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अब घाटों का सौंदर्य क्रूज से निहार सकेंगे और आध्यात्मिक यात्रा का नया अनुभव पाएंगे। लेकिन यह पूरी योजना केवल फोटों और घोषणाओं तक सिमटकर रह गई। हाल यह था कि जब पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह स्वयं इसका उद्घाटन करने पहुंचे, तब भी क्रूज स्टार्ट नहीं हो पाया। बड़ी मशक्कत और दिखावे के बाद उद्घाटन की औपचारिकता पूरी की गई। उसके बाद कुछ दिन चला, लेकिन फिर तकनीकी खराबी का हवाला देकर बंद कर दिया गया।

उद्घाटन के समय

वर्तमान हालत

इसके बाद प्रशासन का बहाना था कि सरयू में पानी की मात्रा कम है। जब पानी बढ़ा, तो तर्क बदल गया अब ज्यादा पानी को खतरा बताकर सेवा स्थगित कर दी गई। आज वही 'जटायु' क्रूज सरयू किनारे बदहाल पड़ा है जंग खाता, उपेक्षा का शिकार। लाखों रुपये की लागत से बना यह प्रोजेक्ट अब फोटोजेनिक टूरिज्म मॉडल का मजाक बनकर रह गया है।

अब जब नवंबर 2025 में राममंदिर में फिर से भव्य समारोह की तैयारी हो रही है, सरकार ने एक बार फिर 'टाइम मरीना', शाही नौका विहार और आध्यात्मिक यात्रा अनुभव जैसे नए नामों से योजनाएं उछाल दी हैं। लेकिन जनता के मन में सवाल वही है–क्या यह भी 'जटायु' की तरह केवल उद्घाटन और घोषणाओं तक सीमित रह जाएगा?

# बाराबंकी में रहस्यमयी ढंग से लापता हुआ तेल कारोबारी परिवार

» पांच मासूम बच्चे भी शामिल

» सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार लखनऊ की ओर जाता दिखा वाहन, कर्ज के बोझ का भी शक

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

बाराबंकी (कुर्सी)। कुर्सी थाना क्षेत्र के बहरौली गांव से एक तेल कारोबारी अपने पूरे परिवार के साथ रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। लापता व्यक्तियों में कारोबारी आजम (32), उनकी पत्नी हाशमी बानो (30) और पांच बच्चे शामिल हैं। मंगलवार सुबह से परिवार का कोई अता-पता नहीं है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

आजम अपने परिवार के साथ गांव से बाहर सरसों तेल के कारखाने में ही रहते थे। मंगलवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने कारखाना बंद देखा और कई बार फोन करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ, तो परिजन मौके पर पहुंचे। जांच करने पर पाया गया कि कारखाने के मुख्य दरवाजे पर बाहर से बेलन लगा था और कमरे के भीतर केवल पति-पत्नी के मोबाइल फोन बेड पर रखे हुए मिले। परिवार का पिकअप वाहन भी मौके से गायब था।

**पांच मासूम भी लापता**

लापता बच्चों की पहचान गुफरान (12), उमेरा (10), हुमैमा (8), अम्मे (3) और उम्मे (1) के रूप में हुई है। सभी बच्चे अपने माता-पिता के साथ कारखाने में ही रहते थे।

**सीसीटीवी फुटेज में मिला सुराग**

पुलिस ने पड़ताल के दौरान आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में आजम मंगलवार रात करीब 9:20 बजे एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में ईंधन भरवाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद उनका वाहन लखनऊ की ओर जाते हुए रिकॉर्ड हुआ। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि परिवार खुद ही कहीं गया है, हालांकि इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है।

**कर्ज के दबाव की आशंका**

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आजम ने स्थानीय साहूकारों से बड़ी रकम का कर्ज ले रखा था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं कर्ज के बोझ या किसी अन्य तनाव के चलते परिवार ने कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा लिया।

**पुलिस जुटी तलाश में**

कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस तकनीकी मदद, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर परिवार की तलाश में जुटी है। अभी तक परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन गुमशुदगी की जांच तेजी से की जा रही है।

# राम नगर में वन विभाग की मिलीभगत से कट रहे हरे पेड़

» नथनापुर पेट्रोल टंकी व कटक गांव के मोड़ के बीच में एक सरकारी विशाल शीशम का पेड़ काटकर नष्ट किया गया

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

बाराबंकी। थाना रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर मार्ग पर नथनापुर पेट्रोल टंकी व कटक गांव के मोड़ के बीच में एक सरकारी विशाल शीशम का पेड़ काटकर नष्ट किया गया। ग्रामीणों ने बताया नाथुनपुर पेट्रोल टंकी 200 मी दाहिनी साइड में एक विशाल शीशम का पेड़ कट कर नष्ट कर दिया।

जब किसान अपने कुछ कार्य के लिए पेड़ काटता है। वन विभाग के अधिकारी किसान पर एफआईआर या जुर्माना की कार्रवाई की जाती एक सरकारी पेड़ टंकी के 200 मी दाहिनी साइड में वन माफिया ने एक विशाल शीशम का पेड़ वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रेंजर मोहित श्रीवास्तव की मिली भगत से कटकर नष्ट कर दिया वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रेंजर द्वारा वन माफिया पर कार्रवाई करते डर लगता है क्योंकि वन माफियाओं व डिप्टी रेंजर का गोपनीय रिस्ता रहता है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है।

वन विभाग के डिप्टी रेंजर मोहित श्रीवास्तव के मिली भगत से आए दिन प्रतिबंध व सरकारी पेड़ वन माफिया द्वारा काटकर नष्ट किया जाता है इसी तरह वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रेंजर मोहित श्रीवास्तव का वन माफियाओं पर सहयोग रहेगा वन माफियाओं का बल्ले बल्ले रहेगा इसी तरह वन माफिया हरियाली नष्ट कर देंगे जिले के अधिकारी डीफो मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई करें पूरा मामला थाना बदोसराय व थाना रामनगर के बॉर्डर का बताया जा रहा है।

# विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

## पीएम, सीएम, राज्यपाल से शिकायत! सेवानिवृत्ति के बाद खुद का किया सेवा विस्तार!

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार दुबे पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सेवा नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोपों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्मेश प्रताप सिंह नामक कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रीना एन सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल समेत अन्य उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि प्रदीप दुबे का कार्यकाल वर्षों पहले समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद वे अवैध रूप से पद पर बने हुए हैं।

**सेवा विस्तार का फर्जीवाड़ा:** शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदीप दुबे की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2019 को निर्धारित थी और इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी। इसके बावजूद, बिना किसी वैध सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति आदेश के वे अब तक पद पर बने हुए हैं। आरटीआई के जरिए प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, उनका कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर खुद को विस्तार दे दिया। इतना ही नहीं, 2019 में एक शपथपत्र में उन्होंने अपनी उम्र 57 वर्ष बताई जबकि वे तब 66 वर्ष पार कर चुके थे।

### मुख्यमंत्री से की सख्त कार्रवाई की मांग

कर्मेश ने मांग की है कि प्रदीप दुबे को तत्काल पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ सीबीआई या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही विधान सभा सचिवालय में की गई अवैध नियुक्तियों की जांच भी त्वरित रूप से करवाई जाए।

**भ्रष्टाचार और नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप :** कर्मेश प्रताप सिंह का कहना है कि प्रदीप दुबे ने विधानसभा में नियुक्तियों की प्रक्रिया में व्यापक हेरफेर की। उन्होंने 2010-2011 में सेवा नियमों में गुप्त तरीके से संशोधन कर लोक सेवा आयोग की भूमिका समाप्त कर दी और नियुक्तियों का पूरा नियंत्रण विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। यह संशोधन कथित रूप से सदन में पेश भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद, उन्होंने हारे हुए विधानसभा अध्यक्ष से नियुक्ति आदेश प्राप्त किया, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना जा रहा है।

**जांच आदेश दबाने और कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप :** शिकायत में यह भी आरोप है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय समेत कई उच्चस्तरीय जांच आदेशों को प्रदीप दुबे ने अपने प्रभाव से दबा दिया। उनके कार्यकाल में कई कर्मचारियों का उत्पीड़न भी सामने आया। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लाल रत्नाकर सिंह को कथित रूप से झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया, जबकि एक अन्य कर्मचारी प्रेमपाल ने उत्पीड़न से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली। सहायक चंद्रप्रकाश को भी मनमाने ढंग से बर्खास्त किया गया।

**कर्मेश प्रताप सिंह की बहाली की मांग :** कर्मेश प्रताप सिंह ने बताया कि वे 14 जुलाई 2016 को सूचना अधिकारी पद पर नियुक्त हुए थे और 2019 में स्थायी कर्मचारी घोषित किए गए। उनका सेवा रिकॉर्ड बेहतर था, लेकिन एक असफल अभ्यर्थी की याचिका के आधार पर बिना किसी जांच या विभागीय कार्रवाई के उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। शिकायत में उन्होंने अपनी तत्काल बहाली, लंबित पदोन्नति और सेवा लाभों की पुनः स्थापना की मांग की है।

---

## एनसीईआरटी की 8वीं की नई किताब में

# 'क्रूर और निर्दयी शासक था बाबर'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**नई दिल्ली।** एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई किताब जारी कर दी है। इसमें दिल्ली सल्तलन से लेकर औपनिवेशिक काल का इतिहास बताया गया है।

आठवीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि इतिहास में मुगलों ने कितने अत्याचार किए थे। बाबर ने कैसे कत्लेआम मचाया। अकबर कितना क्रूर था। और औरंगजेब ने कैसे मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट कर दिया। यह सारे बदलाव हृष्टश्वत्रक्ष ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में किए हैं। इस किताब से छात्रों को दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से रूबरू करवाया जाएगा।

आठवीं क्लास की सोशल साइंस की इस किताब का पहला पार्ट 'Exploring Society' : Indian and Beyond पिछले हफ्ते रिलीज किया गया है। किताब में हुए इस बदलाव पर सवाल भी उठ रहे हैं।

---

## रूस की दो टूक

# मास्को को ट्रंप की धमकी की परवाह नही

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**नई दिल्ली।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर 50 दिनों के भीतर शांति समझौता करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर समझौता नहीं होता है, तो वह रूस पर भारी टैरिफ लगाएंगे। वहीं, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप की चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नाटकीय अल्टीमेटम है और रूस को इसकी कोई परवाह नहीं है। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार देने के लिए एक समझौता कर रहा है।

---

## मानसून सत्र

## कांग्रेस ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति

# सरकार 8 नए बिल लाने की तैयारी में, हंगामे के आसार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**नई दिल्ली।** जहां एक ओर सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में आठ नए बिल पेश करने की तैयारी कर रही है वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। 21 जुलाई से प्रारंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार आठ नए बिल पेश कर सकती है, जिनमें खेल, खनिज, शिक्षा, टैक्स से संबंधित बिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दस जनपथ में कल संपन्न हुई कांग्रेस की बैठक में सत्र के दौरान कांग्रेस की रणनीति पर गहन मंथन हुआ।

### बिहार में मतदाता सूची संशोधन

बिहार में मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विपक्ष पहले से सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को संसद में घेरने की योजना बनाई है।

### कांग्रेस होगी मुखर

मणिपुर से यूपी, मध्यप्रदेश तक महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की योजना बनाई है। महिला सुरक्षा, न्याय और तेजी से कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश करेगा।

संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार आठ नए बिल पेश कर सकती है, जिनमें खेल, खनिज, शिक्षा और टैक्स से जुड़े कानून शामिल हैं. साथ ही, पहले से लंबित आठ बिल को पास कराने का भी प्रयास करेगी, जिसमें इनकम टैक्स बिल 2025 और इंडियन पोर्ट्स बिल सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं।

**कांग्रेस की रणनीति तैयार :** 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। इस बार कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के सीजफायर को लेकर दावे, बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल जांच पड़ताल जैसे पांच प्रमुख मुद्दो पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने दावे को दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया कि व्यापार के जरिए उन्होंने संभावित परमाणु युद्ध टाल दिया था। कांग्रेस पार्टी सरकार से यह सवाल करेगी कि ऐसे मामलों में भारत की विदेश नीति और राजनयिक प्रतिक्रिया कमजोर क्यों रही।

**जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग :** सत्र के दौरान कांग्रेस केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर जोर देगी। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने कई बार इस पर आश्वासन दिया लेकिन कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया।